



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 238]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 31, 1980/पौष 10, 1902

No. 238]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 31, 1980/PAUSA 10, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिसमें कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1980

गत-प्रतिष्ठित नियति अभिमुख एकक

सं० 8/15/78-ई०पी०-व्यापार गेप में बढ़ते हुए घाटे का पूरा करने और विदेशी मुद्रा के रक्षित कोष में जो बराबर कमी आती जा रही है उसे पूरा करने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि अपने निर्यातों में वृद्धि की जाये। तदनुसार सरकार ने गत-प्रतिष्ठित नियति अभिमुखी एककों की स्थापना सुकर बनाने के लिए एक योजना समल में लाने का निश्चय किया है। यह विनिश्चय किया गया है कि इन एककों का कुछ शिपमेंट दी जाये जिससे वे कीमत निर्धारण, क्वालिटी प्रमोजन आदि के मामले में विदेशों की कठोर शर्तों को पूरा कर सकें।

2. गत-प्रतिष्ठित नियति अभिमुख एकक का तात्पर्य एक ऐसे औद्योगिक एकक से होगा जो अपने समस्त उत्पादन का निर्यात के लिये दे दे। इसमें रद्द किये गये माल के स्वीकृत स्तर शामिल होंगे। प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर गत-प्रतिष्ठित नियति करने के लिये स्वीकृत क्रमबद्ध कार्यक्रम की अनुमति होगी। इस प्रकार का एकक एक ऐसे उद्योग से संबंधित होगा जिसकी निर्यात क्षमता और निर्यात लक्ष्यों के बारे में

सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषद ने विचार कर लिया है। संबंधित उत्पाद के संबंध में निर्यात नियंत्रण कंटा मोमार्थे लागू नहीं होंगी। यह मोमार्थे उद्योग के वर्तमान एककों द्वारा पूरी की जा सकेंगी। अभिप्राय यह है कि ऐसी क्षमता का सृजन होना चाहिए जिससे संबंधित निर्यात हों न कि केवल प्रतिस्थापन ही हो।

3. इस प्रकार के एकक में उत्पादन के लिये कम से कम 20 प्रतिशत या उससे अधिक मूल्यवर्द्धन आवश्यक होंगे। मूल्यवर्द्धन का हिसाब लगाने के लिये स्वदेश में प्राप्त वास्तव माल आयात के रूप में माना जायेगा।

4. इस प्रकार के एकक का अनुमोदन करने समय उस प्रतिरिक्त राजभार को भी ध्यान में रखा जाएगा जो प्रस्तावित एकक के द्वारा पूरित होगा।

5. ऐसे उद्योगों को उदाहरण स्वरूप सूची, जिनके बारे में इस योजना के अन्तर्गत विचार किया जा सकता है, संलग्न है।

6. इस योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापित करने के दृष्टिकोण सभी एककों से संबंधित आईएल/एफ सी कार्मों पर औद्योगिक अनुमोदन सांख्यिकीय, उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली को प्रार्थना पत्र देने होंगे। कार्मों के ऊपर "गत-प्रतिष्ठित अभिमुख उद्योग" शब्द लिखे जायेंगे। इन प्रार्थना पत्रों पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा जिसके अध्यक्ष वाणिज्य मंत्री होंगे।

7. थोड़े ड्राग स्वीकृत एकांक पर मोटे तौर पर नियन्त्रित/नियंत्रण शर्त लागू होगी :-

- (1) एकांक द्वारा के अन्तर्गत क्षितिजित करने या शीत सामान्यतः दस वर्ष तक शीत ऐसे उत्पादों के मामले में पांच वर्ष तक जिनमें उच्च कोटि के प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की आवश्यकता हो, शीत उत्पादन वी समस्त भंडा निर्यात करने वी अचन देना । सीमाशुल्क प्राधिकारी इन एकांकों को, चाहे वे कहीं भी स्थित हों, शीत सुविधायी प्रदान करेंगे ।
- (2) पूंजीगत माल, सघटक और कच्चे माल के आयात पर आयात शुल्क की छूट होगी । तैयार माल पर भी उत्पादन शुल्क और अन्य केन्द्रीय कर नहीं लगेंगे ।
- (3) इन नियमों पर नकद महायन्त्र, प्रतिपुति लाइसेंस जैसे कोई नियम लागू नहीं मिलेंगे ।
- (4) आवश्यकतानुसार पूंजीगत माल, सघटकों, कच्चे माल और खपत में आने वाली चीजों के निर्यात की अनुमति होगी ।
- (5) आवश्यक पूंजीगत माल के आयात की अनुमति मुख्य शिपिंग मुद्रा या द्विपक्षीय शर्तों के आधार पर इस प्रकार होगी जिसमें एकांकों की लागत अनुचित रूप से न बढ़ जाए ।
- (6) प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर विवेकी सहाय की अनुमति दी जा सकती है ।
- (7) अधिक काम विभाग की दिनांक 19 फरवरी, 1972 का प्रेम टिप्पणी में विवेकी शिपिंग के काम करने की जो शर्तें निर्धारित की गई हैं वे शत-प्रतिशत निम्न अधिमूल्य कारखानों के मामलों में लागू नहीं की जाएगी ।
- (8) निर्यात उत्पादन पर लाभ की दरों को प्रतिपुति बनाने रखने की दृष्टि से निर्यात एकांकों को और साथ ही वी घरानों/एम आर टी पी एंटी के वित्तीय संस्थाओं में सामान्य शर्त/शिपिंग अनुदान पर उधार लेने की अनुमति दी जा सकती है ।
- (9) स्वदेश में उपलब्ध पूंजीगत माल, सघटक तथा कच्चे माल की अनुमति केन्द्रीय उत्पादन शुल्क वी भुगतान किंसे घिना होगी ।
- (10) 5 प्रतिशत अथवा उनके प्रतिशत तक जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए अस्वीकृत माल के वरेलू टैरिफ क्षेत्र में आयातित अन्तिमिष्ट साधनों पर सीमाशुल्क तथा स्वदेशी अन्तिमिष्ट साधनों पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और साथ ही अस्वीकृत माल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का भुगतान करके या इन करों के कुल योग के बाहर राशि का भुगतान करके वेचने की अनुमति दी जा सकती है ।
- (11) शत प्रतिशत निम्न प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध कार्यक्रम के बारे में गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है । तथापि ऐसे मामलों में उत्पाद वी काम में काम तीन चौथाई अथवा उनमें मात्रा निर्यात करना पड़ेगा ।
- (12) निर्यात शर्त प्राप्त करने की तैयारी की शर्तों वी वर्षों में अचन नहीं होगी तथा भुगतान की शर्तों के अनुसार निर्यात दायित्व की शर्त तैयारी की शर्तों के बाद आरंभ होगी ।
- (13) निर्यात दायित्व की शर्त के बारे में बोर्ड द्वारा समीक्षा की होगी तथा इस प्रण के बारे में विवेकी किसी एकांक को निर्यात दायित्व की शर्तों के पूरा होने के बाद बांड मुक्त होने की अनुमति दी जा सकती, और इसके बाद वरेलू बाजार के लिए उत्पादन करने की अनुमति दी जा सकती, उस समय लागू औद्योगिक नीति, शिपिंग भागीदारी, स्वदेशी अम्ल तथा लघु उद्योग को संरक्षण को देखते हुए निर्णय किया जाएगा ।

(14) निर्यात की शर्तों के बाद बांड मुक्त करने पर शर्त निम्नोक्त प्रकार से लगाया जाएगा :-

- (क) पूंजीगत माल के शर्त मूल्य पर सीमाशुल्क परन्तु उन वरी पर जो आयात के समय प्रचलित थी;
 - (ख) अप्रयुक्त आयातित कच्चे माल तथा सघटकों पर उक्त मूल्य पर सीमाशुल्क लगाया जाएगा जो आयात के समय था और उन दरों पर लगाया जाएगा जो विवरण के समय प्रचलित था
 - (ग) उत्पादन शुल्क लगाये जा सकने योग्य माल के सबध में उत्पादन शुल्क बिना मुख्य ज्ञान के लगाया जायेगा और उस दरों पर लगाया जाएगा जो विवरण के समय रही हो ।
- (15) औद्योगिक लाइसेंस के लिए औद्योगिक अनुमति संचालन का भेजा गया अचन पत्र एम आर टी पी अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र माना जायेगा और उसकी प्रोसेस करने के लिए एक मास कार्यवाही की जायेगी ताकि बांड द्वारा एक ही स्थान पर विवरण दी जा सके ।
- (16) यदि इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कोई एकांक किसी कारणों से इस योजना के अन्तर्गत अपने निर्यात संबंधी या अन्य दायित्वों का पूरा करने में असमर्थ है, तो बोर्ड उस एकांक को परस्मिन्धों का पुनर्विलोकन करेगा और इस बात की सिकारिण करेगा कि इस एकांक के सबध में भविष्य में क्या कार्यवाही की जाए ।
- (17) जो एकांक इन विशेष सुविधाओं के लिए मजूर किए जायेंगे वे आयात निर्यात के मुख्य निर्यात को बांड/कानूनी दखनद पर कर देंगे और यदि वे कर उल्लंघनियों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो वे आयात व्यापार निरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत उन पर कोई जुर्माना डाला जा सकता हो तो इसके अलावा उन पर इस प्रकार के बांड/कानूनी दखनद के अनुसार भी जुर्माना डाला जा सकता है ।

शत-प्रतिशत निर्यात के आधार पर विशेष सुविधाओं के जो उत्पाद पाव हों उनकी उदाहरणस्वरूप सूची

1. इंजीनियरी माल

- 1.1 इंजीनियरी माल (प्रारंभ और अन्तिम धातुओं का छोड़कर)
- 1.2 इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद जिनमें इलेक्ट्रॉनिकों कोकटेयर शामिल हैं ।

2. रसायन एंजाइम के उत्पाद तथा संसाधन उत्पाद अथवा :-

- (क) अकार्बनिक रसायन कार्बनिक रसायन एवं विविध रसायन ।
- (ख) औषध एवं औषध सघटकों पदार्थ जिनमें अन्तर्गत औषध शामिल हैं ।
- (ग) रजक एवं रजक संयोजक पदार्थ ।
- (घ) प्रसाधन सामग्री तथा सुगंध सामग्री (साधारण टास्क का छोड़ कर) ।
- (ङ) पेठ और संबंधित उत्पाद ।
- (च) सेटी माचिस, आतिशबाजी, स्फोटक पदार्थ, अधिस्फोटक पदार्थ ।

- (छ) सिरेमिक उत्पाद ।
 - (ज) बाँस तथा कान के तंतु ।
 - (झ) लकड़ी की चीजें प्राथमिक रूप से ।
 - (ण) गन्ने-होंठों, गोबर, जिनमें एकतरफा और सीसे के चीजे शामिल हैं ।
 - (ट) रबर की चीजे ।
 - (ठ) कागज, कागज के उत्पाद और लेखन सामग्री ।
 - (क) कोटकाक दवाई और परिरक्षण दवायें ।
 - (ख) अन्नबालियाँ ।
- 2.2 पान संबंधी आयात-रिजिस्ट्रेशन ।
 - 2.3 अन्नसहस्रें ।
 - 2.4 प्लास्टिक और लिनेनियम उत्पाद ।
3. फर्नीचर :
 4. चमड़े का और खेचकूद का सामान :
 - 4.1 सैयान चमड़ा और चमड़े की चीजें, जिनमें फुटवियर और पैट ब्रश शामिल हैं ।
 - 4.2 खेचकूद का सामान ।
 5. खाद्य, कृषि तथा वन उत्पाद :
 - 5.1 डिब्बाबन्द तथा बर्क से जमे हुए संस्कृति उत्पाद ।
 - 5.2 सांघित खाद्य पदार्थ, फल, सब्जियाँ तथा अलकोहल वाले और अमिश्रक पेय ।
 - 5.3 मांस तथा संबंधित उत्पाद ।
 - 5.4 पैकेजबन्द चाय, अर्थात् एक किंवा ग्राम तक के उद्देश्यता पैकों में पैक की हुई चाय तथा इम्पेट चाय ।
 - 5.5 पिसी हुई इम्पेट और पैकेजबन्द चाय ।
 - 5.6 तम्बाकू उत्पाद ।
 - 5.7 चावल की तेल रहित भूसी और बिनीले को खरी, माल के थोड़ी की बसा और पशु खाद्य पदार्थ ।
 - 5.8 आम की गिरी का निष्कारण और आम की गिरी का तेल ।
 6. वस्त्र
 - 6.1 कान्चीन
 - 6.2 स्निग्धिलाय परिधान, स्टिचियन तैयार चीजे ।
 - 6.3 रबड़ फुका बयार और कलई बयार ।
 - 6.4 खादी ।
 - 6.5 प्राकृतिक रेशम के वस्त्र परिधान तथा सैयार चीजे ।
 - 6.6 हूँजरी ।
 - 6.7 हथकरघा वस्त्र, तैयार चीजे और परिधान ।
 7. विविध :
 - 7.1 हस्तशिल्प की वस्तुएँ ।
 - 7.2 चाभी और सोने के आभूषण ।
 - 7.3 पैपरकॉटिड आभूषण ।

के० प्रकाश प्रानन्द, संपूजित सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st December, 1980

100 Per Cent EXPORT ORIENTED UNITS (I)

S.O. No. 815/78-EP.—In order to bridge the increasing deficit in the balance of trade and running down of exchange reserves, it has become necessary to step up the growth of

our exports. Accordingly Government have decided to implement a scheme to facilitate the setting up of 100 per cent export oriented units. It has been decided to give such units certain concessions to enable them to meet rigours of foreign demand in terms of pricing, quality precision etc.

2. A 100 per cent export oriented unit would imply an industrial unit offering for exports its entire production excluding permitted levels of rejects. An agreed time-phasing for achieving 100 per cent export will be permissible on merits of each case. Such an unit would belong to an industry in respect of which the export potential and export targets have been considered by the relevant Export Promotion Council. The product concerned should not be subject to export control, and the unit should not be reached by existing units in the industry. The intention is that capacity should be created which should result in additionality of exports and not mere substitution.

3. Minimum value added content of 20 per cent or more will be necessary for production of such a unit. Domestically procured raw materials shall be treated as imports for computation by value added.

4. While approving such a unit the additional employment which would be generated by the proposed unit would also be taken into consideration.

5. An illustrative list of industries which may be considered under the scheme is annexed.

6. All the units intending to set up industries under the scheme shall make applications to the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Industry, Department of Industrial Development, Udyog Bhavan, New Delhi in the relevant IL/FC forms super imposed with the words "100 per cent export oriented unit". These applications will be considered by a Board headed by the Commerce Secretary.

7. A unit approved by the Board shall be governed broadly by the following terms and conditions :—

- (i) The unit shall undertake to manufacture in bond and to export its entire production for a period of 10 years ordinarily and 5 years in the case of products having high degree of technological change. The Customs Authorities shall provide bond facilities to such units wherever located.
- (ii) Import of capital goods, components, and raw materials shall be exempt from import duty. Finished products shall also be exempt from excise and other central levies.
- (iii) No export benefits like cash assistance, replenishment licences would be admissible on these exports.
- (iv) Import of capital goods, components, raw materials and consumables, as required will be permitted.
- (v) Imports of necessary capital goods shall be allowed against free foreign exchange or bilateral credits in such a way that the cost of units is not unduly raised.
- (vi) Foreign collaboration may be permitted on merits of each case.
- (vii) The conditions for dilution of foreign equity as stipulated in the Department of Economic Affairs Press Note of 17th February, 1972, will not be enforced in 100 per cent export oriented cases.
- (viii) So as to keep rates of return on export production competitive, exporting units including Large Houses, MRTD units may be permitted to borrow from financial institutions at normal debt/equity ratio.
- (ix) Indefinitely available capital goods, components and raw materials will be allowed without payment of Central Excise Duty.
- (x) Rejects up to 5% or such percentage as may be fixed by the Board may be allowed to be sold in the domestic tariff area on payment of customs duty on imported inputs and Central Excise Duty on the indigenous inputs and also Central Excise Duty on the rejects for an amount equal to the aggregate of such duties.

- (xi) Time phasing for achieving 100 per cent exports may be considered on merits. However, in such cases exports shall have to be at least three-fourths or more of the production.
- (xii) The gestation period for achieving export targets shall not be more than two years and the period of export obligation in terms of the approval shall commence after the gestation period.
- (xiii) The condition of export obligation shall be subject to review by the Board and the question whether the unit can be allowed to be debonded after completion of export obligation period and thereafter allowed to produce for domestic market shall be decided in the light of industrial policy in force at that time, equity participation, indigenous capacity and protection to small scale industry.
- (xiv) On debonding after the period of export, duties shall be leviable as follows :—
- (a) customs duty on capital goods on the depreciated value but at rates prevalent at the time of import;
 - (b) customs duty on unused imported raw materials and components on value at the time of import and rates in force at the time of clearance; and
 - (c) in respect of excisable goods, excise duty to be levied without depreciation and at rate attracted at the time of clearance
- (xv) An application made for industrial licence to the Secretariat for Industrial Approvals shall be treated as an application under the MRTP Act, 1969 and simultaneous action shall be taken to process the same so that a single point clearance is given by the Board.
- (xvi) If any unit approved under this scheme is unable for any reasons, to fulfil its export or other obligations under this scheme, the Board will review the circumstances of that unit and recommend the future course of action to be taken in regard to that unit.
- (xvii) The units which are approved for these special facilities would have to execute bond/legal undertaking with the CCI&F and in case of failure to fulfil their obligations, they would be liable to penalty in terms of such bond/legal undertaking besides the penalty, if any, under the Import Trade Control Regulations.
- ILLUSTRATIVE LIST OF PRODUCTS WHICH WOULD BE ELIGIBLE FOR SPECIAL FACILITIES ON THE GROUND OF 100 PER CENT EXPORTS**
1. Engineering goods :
 - 1.1 Engineering goods (excluding prime and non ferrous metals).
 - 1.2 Electronics products including electronic software.
 2. Chemicals, Plastics and Allied Products, namely :
 - (a) Inorganic chemicals, organic chemicals and miscellaneous chemicals.
 - (b) Drugs and drugs intermediates, including crude drugs.
 - (c) Dyes and dye intermediates.
 - (d) Toiletaries and perfumeries (excluding processed talc).
 - (e) Paints and allied products.
 - (f) Safety matches, fireworks, explosives and detonators.
 - (g) Ceramic products.
 - (h) Glass and glassware.
 - (i) Wood products and processed wood.
 - (j) Asbestos, cement, including clinkers and cement products.
 - (k) Rubber manufactures.
 - (l) Paper, Paper products and Stationery.
 - (m) Pesticides and preservatives.
 - (n) Agarbattis.
 - 2.2 Culinary oleo-resins.
 - 2.3 Refractories.
 - 2.4 Plastics and Linoleum Products.
 3. Furniture.
 4. Leather and Sports Goods :
 - 4.1 Finished leather and leather manufacturers, including footwear and Paint Brushes.
 - 4.2 Sports goods.
 5. Food, Agriculture and Forest Products :
 - 5.1 Canned and frozen marine products.
 - 5.2 Processed foods, fruits, vegetables and alcoholic and soft beverages.
 - 5.3 Meat and allied products.
 - 5.4 Packaged tea i.e. tea packed in consumer packs of a size upto 1 kg. and instant tea.
 - 5.5 Instant and packaged ground coffee.
 - 5.6 Tobacco manufactures.
 - 5.7 Deoiled rice bran and cotton seed cakes, Sal seed fats and animal foods.
 - 5.8 Mango Kernel Extraction and Mango Kernel Oil
 6. Textiles :
 1. Carpets.
 2. Readymade garments, knitwear, made-up articles.
 3. Rubberised coir and curled coir.
 4. Khadi.
 5. Natural silk fabrics, garments and made-up articles.
 6. Hosiery.
 7. Handloom fabrics, made-up articles and garments.
 7. Miscellaneous :
 1. Handicrafts.
 2. Silver and Gold Jeweller.
 3. Fabricated Mica.

K. PRAKASH ANAND, Jt. Secy.